



2026:AHC-LKO:17511-DB

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

लखनऊ

विशेष अपील सं. - 128/2026

दीपक त्रिपाठी

....अपीलकर्ता (गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य, प्रमुख सचिव, पंचायत राज विभाग,  
लखनऊ के माध्यम से और 3 अन्य

..... प्रतिवादी (गण)

---

अपीलकर्ता (गण) के अधिवक्ता : पी.के. मिश्रा

प्रतिवादी (गण) के अधिवक्ता : सी.एस.सी., लल्ला जी मौर्य

---

**न्यायालय सं. - 1****माननीय न्यायमूर्ति राजन राय****माननीय न्यायमूर्ति अबधेश कुमार चौधरी**

1. सुना गया।

2. यह इलाहाबाद उच्च न्यायालय नियमावली, 1952 के अध्याय VIII नियम 5 के अंतर्गत एक अपील है, जो रिट-सी सं. 107/2026 'अनिल कुमार बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य' में पारित दिनांक 05.02.2026 के निर्णय और आदेश के विरुद्ध है।

3. पक्षकारों को सुनने और अभिलेख, जिसमें आक्षेपित निर्णय भी शामिल है, का अवलोकन करने के बाद, हमने पाया कि अपीलकर्ता, यद्यपि ग्राम पंचायत का सदस्य है, अन्य

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



पिछड़ा वर्ग श्रेणी से संबंधित नहीं है; जबकि ग्राम प्रधान का पद, जिस पर मृतक-ओरी लाल निर्वाचित हुए थे, अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी के लिए आरक्षित था। इसलिए, हमें विद्वान एकल न्यायाधीश के निर्णय में कोई त्रुटि नहीं दिखती, जब उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम, 1947 की धारा 12-जे के अंतर्गत कार्यवाहक उद्देश्यों के लिए भी, भले ही ग्राम पंचायत के सदस्यों के परामर्श से, केवल अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी के व्यक्ति को ही ग्राम प्रधान के रूप में कार्य करने का निर्देश दिया जा सकता था। जहाँ तक अपीलकर्ता के अधिवक्ता की इस दलील का प्रश्न है कि ग्राम पंचायत के अन्य सदस्यों के साथ परामर्श के लिए कोई निर्देश जारी नहीं किया गया है, ऐसा प्रतीत होता है कि निर्णय के मुख्य भाग में सीतापुर के जिला मजिस्ट्रेट/डीपीआरओ को निर्देश दिया गया है कि वे उक्त निर्णय में की गई टिप्पणियों को ध्यान में रखते हुए कार्यवाहक प्रधान की नई नियुक्ति करें, और निर्णय के मुख्य लेख में, विद्वान एकल न्यायाधीश ने 'उदयवीर बनाम राज्य निर्वाचन आयोग, उ.प्र.' (2008) एससीसी ऑनलाइन ऑल 2132, 'पुष्पेंद्र कुमार बनाम उत्तर प्रदेश राज्य' (2010) एससीसी ऑनलाइन ऑल 3140 और 'श्याम बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य' (2010) एससीसी ऑनलाइन ऑल 1250 वादों में व्यक्त विचारों से सहमति जताई है, इसलिए, यह दलील सही नहीं है। अतः, हमें आक्षेपित निर्णय में कोई त्रुटि नहीं मिली।

4. तदनुसार, अपील खारिज की जाती है।

(न्यायमूर्ति अबधेश कुमार चौधरी) (न्यायमूर्ति राजन राय)

10 मार्च 2026

शानू/-

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।